को ध्यान में रख कर किया जाता है । कोषागारों/उप कोषागारों के नकद कारबार को संबंधित केन्द्रों में कार्य कर रही सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं में स्थानांतरित करने के लिए राज्य सरकार(रों) से प्राप्त अनुरोधों पर संबंधित बैंकों के साथ परामर्श करके भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विचार किया जाता है।

सरलीकृत आयकर कानून

4427. **श्री राजवंती :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरलीकृत नया आयकर कानून बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक अधिनियमित कर दिया जाएगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस मामले पर भविष्य में विचार करने का विचार रखती है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) आयकर कानून का सरलीकरण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।

विदेशी ऋणों का भुगतान

4428. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार मूलधन तथा इस पर ब्याज सहित प्रति वर्ष चुकता किए जा रहे विदेशी ऋण का ब्यौरा क्या है; और

(ख) 31 मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार, भारत पर विदेशी ऋण की कुल कितनी धनराशि थी और इसे चुकता करने की क्या प्रक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) मूलधन की वापसी/अदायगी और विदेशी ऋण पर ब्याज का भुगतान जिसमें रक्षा ऋण और अनिवासी भारतीय जमा राशियां शामिल हैं, क्रमशः 1990-91 में 4.46 बिलियन अमरीकी डालर और 3.67 बिलियन अमरीकी डालर, 1991-92 में 4.53 बिलियन अमरीकी डालर और 3.68 बिलियन अमरीकी डालर और, 1992-93 में 4.45 बिलियन अमरीकी डालर और 3.72 बिलियन अमरीकी डालर था । 1993-94 के दौरान मूलधन की वापसी / अदायगी की राशि और ब्याज का भुगतान 4.55 बिलियन अमरीकी डालर और 3.71 बिलियन अमरीकी डालर होने का अनुमान है ।

(ख) नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, देश पर कुल बकाया विदेशी ऋण, जिसमें रक्षा ऋण और अनिवासी भारतीय जमा राशियां भी शामिल हैं, सितम्बर, 1993 के अंत तक 90.386 बिलियन अमरीकी डालर होने का अनुमान है । विदेशी ऋणों की वापसी / अदायगी दाता एजेंसियों के साथ परस्पर सहमति से प्रत्येक ऋण समझौते के नियम व शर्तों के अनुसार निर्धारित तिथियों पर ही की जाती है।

केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में भर्ती पर प्रतिबंध

4429. **श्री एस० आस्टिन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में विभिन्न पदों/श्रेणियों के अन्तर्गत नई भर्ती किये जाने पर रोक लगाई गई है;

(ख) यदि हां, तो कब से रोक लगाई गयी है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार इस प्रतिबन्ध को हटाने का विचार रखती है ;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भर्ती पर सामान्य तौर पर कोई रोक नहीं है । तथापि, मितव्ययिता बरतने सम्बन्धी उपायों के एक भाग के रूप में मई, 1993 में इस आशय के अनुदेश जारी किए गए थे कि उन पदों को जो एक वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि के लिए रिक्त पड़े हुए हैं, समाप्त हुआ समझा जाएगा और यदि आवश्यकता महसूस होती है तो पदों के सृजन की निर्धारित प्रक्रिया अपनाने के बाद उन्हें पुनः सृजित किया जा सकता है।

(ख) से (ङ) : प्रश्न नहीं उठते ।

Regional Rural Banks in Tamil Nadu

4430. SHRI S. AUSTIN : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the numbers and locations of the Regional Rural Banks functioning in Tamil Nadu ;

(b) the main objectives of these banks and the extent to which these objectives have been achieved during the last two years ;

(c) whether some of these banks are facing financial crisis ;

(d) if so, the reasons therefor ; and

(e) the measures taken by Government to improve the performance of the above banks ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY) : (a) There are three Regional Rural Banks (RRBs) operating in the State of Tamil Nadu having a network of 208 branches as at the end of March, 1993 with headquarters located at Sattur, Dharmapuri and Cuddalore.

(b) The main objectives of the RRBs are :—

(i) to take the banking services to the door steps of rural masses particularly in hitherto unbanked areas,

(ii) to make available institutional credit to the weaker sections of the society,

(iii) to mobilise rural savings and channelise them for supporting productive activities in the rural areas,

(iv) to create supplementary channel for flow of credit from the central money market to the rural areas throuh refinance,

(v) to generate employment opportunities in rural areas, and

(vi) to bring down the cost of purveying credit in rural areas

As of March, 1993, as much as Rs. 8076 lacs were mobilised by RRBs in 5.76 lac accounts in Tamil Nadu. The credit support provided by these banks amounted to Rs. 8220 lacs (Outstanding) in 2.31 lac accounts. Thus over a period of time, the RRBs have achieved significant growth in taking banking services to the door steps of the rural poor, providing them with institutional credit support and mopping up of hitherto untapped rural savings.

(c) and (d) In the process of reaching to the weaker sections and fulfilling the broad socio-economic objectives, these RRBs have suffered financially. All the banks put together in Tamil Nadu have incurred a loss of Rs. 627.13 lacs during 1992-93 and their accumulated losses stood at Rs. 1452.24 lacs, as at the end of March, 1993. The reasons for incurring losses by RRBs are attributable to several factors like restriction on the choice of clientele, limited area of operation, low interest margins, mounting establishment costs particularly after implementation of the award of the National Industrial Tribunal etc.

(e) With a view to improving their viability in the short term a package of measures has been announced in December, 1993. These measures include raising non-target group financing from 40 per cent to 60 per cent, increasing non-fund business, freeing RRBs whose disbursals during 1992-93 were less than Rs. 2 crores from service area obligations and permitting them to relocate loss making branches at places like Mandis, Taluk/District headquarters, agriculture produce centres, etc. and to open extension counters at premises of institutions for which the RRB is the principal banker. The RRBs have also been permitted to install safe deposit lockers.

Simplification of Procedure by Central Board of Direct Taxes

4431. SHRI S. AUSTIN : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether the Central Board of Direct Taxes is streamlining and simplifying various procedures to create an atmosphere of mutual trust and confidence between the assessees and assessing authorities ; and

(b) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY) : (a) and (b) Yes, Sir. The Central Board of Direct Taxes has been taking steps from time to time to streamline and simplify the procedures so as to create an atmosphere of mutual trust and confidence between the assessees and the department. Some salient steps taken in this regard are as follows :—

(i) A simplified summary assessment scheme is in operation with effect from assessment year 1989—90 under which about 97 per cent of the returns are accepted with only prima facie adjustments, thereby dispensing with the need for the taxpayers to attend I.T. Offices.